नवोन्मेष

रुक्टा (राष्ट्रीय)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org **Fax No.:** +91-8302542605

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : के. 52, कृष्णगंज, **अजमेर-305001**

दूरभाष : अध्यक्ष : डॉ. ग्यारसीलाल जाट, सीकर (01572) 245866, मो. 9414038866

महामंत्री : डॉ. मधुर मोहन रंगा, अजमेर (0145) 2429341, मो. 9414008425

परिपत्र क्रमांक : रुक्टा (रा.)/2011-12/4 **दिनांक: 31 जनवरी 2012**

(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

प्रिय महोदय/महोदया

सादर नमस्कार!

कोटा के राजकीय महाविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, जे.डी.बी महिला महाविद्यालय, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय व माँ भारती बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 14 व 15 जनवरी 2012 को माँ भारती सीनीयर सैकण्ड्री स्कूल, स्वामी विवेकानंद नगर, कोटा में सम्पन्न 50वें स्वर्ण जयंती अधिवेशन के विस्तृत विवरण, अधिवेशन हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश के आदेश, यू.जी.सी. वेतनमानों के संबंध में प्रबन्ध समितियों को निर्देश के आदेश, 50वें प्रांतीय अधिवेशन में प्रस्तुत महामंत्री प्रतिवेदन तथा 30 जून 2011 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित खाते व बैलेंस शीट के साथ परिपत्र प्रेषित है।

1. **रुक्टा (राष्ट्रीय) का 50वाँ स्वर्ण जयंती अधिवेशन सम्पन्न :-** राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का 50वाँ प्रांतीय स्वर्ण जयंती अधिवेशन 14 व 15 जनवरी 2012 को कोटा में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में राज्य के सभी जिलों के राजकीय व गैर अनुदानित महाविद्यालयों के साथ-साथ चार विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिवेशन में रुक्टा (रा) के पूर्व अध्यक्षों, पूर्व महामंत्री, सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित 400 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री व शैक्षिक संवाद के प्रधान सम्पादक ने अधिवेशन में भाग लेकर शिक्षकों का उत्साहवर्द्धन किया।
2. **प्रान्तीय अधिवेशन का शुभारम्भ :-** 50वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष व विधायक श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रदेश भा.ज.पा. अध्यक्ष श्री अरुणजी चतुर्वेदी व विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री प्रो. जे.पी. सिंघल ने माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन व भारत माँ के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कोटा विश्वविद्यालय की छात्राओं ने वंदेमातरम् व सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। आयोजन अध्यक्ष प्रो. सुरेशचन्द राजोरा ने सभी का अभिनंदन करते हुए स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष श्री महेशजी विजय, संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री, आयोजन अध्यक्ष व आयोजन

सचिव ने अतिथियों का स्वागत किया। रुक्टा (रा) के अध्यक्ष ने राज्य में शिक्षा के विभिन्न आयामों एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, उन्होंने मकर संक्रान्ति की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि संगठन सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों के साथ साथ वैचारिक प्रबोधन के कार्यक्रम भी करता है। संगठन के महामंत्री ने संगठन की वर्ष भर की गतिविधियों का विवरण देते हुए राज्य में उच्च शिक्षा की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा आगामी चुनौतियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 6 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री घनश्यामजी तिवाड़ी ने कहा कि शिक्षा से समाज व राष्ट्र का निर्माण होता है, यह तभी संभव है जब शिक्षा सुसंस्कार व राष्ट्रीय संस्कृति से जुड़ी हो। उन्होंने चाणक्य, चरक, चन्द्रगुप्त मौर्य व महाराणा प्रताप आदि के उदाहरण देते हुए उनके कृतित्व से शिक्षा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा को युगानुकूल व देशानुकूल बनाने से ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन की बात कही, साथ ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक निष्पक्ष नियामक निकाय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज समाज में सैद्धान्तिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है अत: उचित शिक्षा प्रणाली ही इन मूल्यों को पुन: स्थापित कर सकती है। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री अरुणजी चतुर्वेदी ने कहा कि उचित शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता है, शिक्षा केवल कॅरियर बनाने वाली नहीं होनी चाहिये, शिक्षा संस्कार युक्त व्यक्ति निर्माण करने वाली होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि उपाधि को नौकरी से नहीं जोड़ना चाहिये, समाज हमसे अपेक्षा करता है कि संस्कारों के सृजन में हमारा महत्वपूर्ण योगदान हो, जिससे सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव हो सके। उनका विचार था कहा कि भारतीय दर्शन व चिंतन से ही संस्कार निर्माण होंगे, अत: इनका शिक्षा में समावेश किया जाना चाहिये। उन्होंने आह्वान किया कि हम अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य की भी बात करें। स्वर्ण जयंती अधिवेशन पर अतिथियों को स्मृति चिह्न प्रदान किये गये। उद्घाटन कार्यक्रम में कोटा के गणमान्य नागरिकों के अतिरिक्त विधायक श्रीमती चद्रकांता मेघवाल भी उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त सचिव डॉ. नारायणलाल गुप्ता ने किया। धन्यवाद आयोजन सचिव डॉ. दिलीप गोयल ने दिया।

3. **स्मारिका का विमोचन :-** स्वर्ण जयंती अधिवेशन के अवसर पर मुख्य अतिथि व कार्यक्रम अध्यक्ष ने स्मारिका 'नवोन्मेष' का विमोचन किया। स्मारिका में राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्रीजी, नेता प्रतिपक्ष, शिक्षा मंत्रीजी व वर्धमान खुला विश्वविद्यालय के कुलपति की शुभकामनाओं के साथ-साथ विद्वानों के शिक्षा से संबंधित लेखों का प्रकाशन किया गया है। स्मारिका में संगठन की अब तक की यात्रा के साथ अन्य जानकारियाँ भी संकलित की है।

4. **संगठन के प्रतीक चिह्न का लोकार्पण :-** उद्घाटन समारोह में संगठन के प्रतीक चिह्न का लोकार्पण मुख्य अतिथि व कार्यक्रम अध्यक्ष ने किया। जिस पर संगठन का ध्येय वाक्य **''संहति: कार्यसाधिका''** अंकित है।

5. **देराश्री स्मृति व्याख्यानमाला में प्रो. पाण्डे का व्याख्यान :-** प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर इस वर्ष का देराश्री स्मृति व्याख्यान रुक्टा (रा.) के पूर्व महामंत्री व शैक्षिक मंथन के प्रधान संपादक प्रो. संतोष पाण्डे ने दिया। समारोह की अध्यक्षता विधायक प्रो. फूलचन्द भिण्डा ने की। प्रो. सत्यदेव देराश्री

के चित्र पर मुख्यवक्ता व कार्यक्रम अध्यक्ष ने माल्यार्पण किया। संगठन के महामंत्री ने प्रो. सत्यदेव देराश्री के जीवन वृत का परिचय कराया। प्रो. संतोष पाण्डे ने कहा कि आज शिक्षा चिंताजनक अवस्था में है, क्योंकि आज की शिक्षा संस्कार देने में विफल रही है। अत: शिक्षा नीति में परिवर्तन संस्कार सापेक्ष होना चाहिये। शिक्षा पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए व राज्य सरकार द्वारा उचित दिशा प्रदान की जानी चाहिये। शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण राज्य व केन्द्र सरकार नीति तय करते हैं, जिसमें कभी-कभी आपसी समन्वय नहीं रहता। आज की शिक्षा 'पैकेज के रोजगार' देने वाली बन गई है, जबकि शिक्षा के द्वारा सांस्कृतिक परम्पराओं का अगली पीढ़ियों में संप्रेषण होना चाहिये। उन्होंने शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देखने वाले शिक्षा माफिया के पनपने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आधारभूत विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिये, ताकि 'स्पेशिलाइज्ड कोर्स' के अध्ययन में सहायता मिले। उच्च शिक्षा में नामांकन की होड़ को कम कर, गुणात्मक शिक्षा व शोध पर बल देना चाहिये। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रो. फूलचन्द भिण्डा ने कहा कि आज एकात्मक शिक्षा नीति की आवश्यकता है नैतिकता, सदाचार व आध्यात्मिकता की शिक्षा से ही संस्कारों का निर्माण होगा। सांस्कृतिक धरोहर को आधार बना कर शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे श्रेष्ठ भारतीय का निर्माण हो। उन्होंने योग शिक्षा को शिक्षा का अनिवार्य भाग बनाने पर जोर दिया व कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ही देश का सर्वांगीण विकास होगा। संगठन के अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया।

6. **प्रतिनिधियों की बैठक सम्पन्न :-** 14 जनवरी को सायंकाल शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में रुक्टा (रा.) की विभिन्न इकाईयों द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। यू.जी.सी. का बकाया 40 प्रतिशत एरियर का भुगतान अविलम्ब करने की माँग के साथ ही पदनाम परिवर्तन नहीं किये जाने, पूर्व सेवा का लाभ नहीं देने व पीएच.डी. उपाधिधारियों को सी.ए.एस. के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोत्साहन वेतन वृद्धियों को यू.जी.सी. की अनुशंषाओं के विपरीत बकाया सहित वापिस लेने पर आपत्ति व्यक्त की गई। नियुक्ति के समय एम.फिल्, पीएच.डी. धारकों को वेतनवृद्धि देने, शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात 1:60 रखने, पूर्व व अन्यत्र की गई सेवा का लाभ प्रदान करने, वरिष्ठ व चयनित वेतनमानों के पात्र शिक्षकों के लिए संवीक्षा बैठक आयोजित करने, सेवारत शिक्षकों को शोध कार्य हेतु कोर्स वर्क से मुक्त करने, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की संशोधित डी.पी.सी. शीघ्र करवाने आदि विषयों पर कार्यवाही का आग्रह किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन पुन: निर्धारण, परिवीक्षा काल में स्थाई सेवा के सम्पूर्ण लाभ प्रदान करने, संविदा पर लगे शिक्षकों की समस्याओं, अकादमिक अवकाश स्वीकृति का अधिकार प्राचार्यों को देने, महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर तुरन्त भर्ती प्रारम्भ करने, शोध को बढ़ावा देने, यू.जी.सी. के सम्पूर्ण पैकेज को लागू करने, परीक्षा पारिश्रमिक में एकरूपता के साथ वृद्धि, आमेलित शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। निजी महाविद्यालय में राजकीय महाविद्यालय अजमेर के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति एवं वरिष्ठता को नजरअंदाज कर कनिष्ठ व्याख्याता को प्राचार्य का पदभार देने पर भी आपत्ति व्यक्त की गई। शिक्षक कल्याण कोष से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को सहायता प्राप्त नहीं होने, कतिपय महाविद्यालयों में वेतन समय पर न मिलने, यू.जी.सी. वेतनमान मिलने से वंचित रहे पुस्तकालाध्यक्षों के संबंध में न्यायालय के निर्णय की पालना न होने का विषय भी प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षकों को

यू.जी.सी. के बकाया एरियर का भुगतान नहीं होने पर शीघ्र कार्यवाही का आग्रह किया गया। महामंत्री ने संगठन द्वारा किये प्रयासों को प्रस्तुत किया व अन्य सुझावों को रचनात्मक बताते हुए इन सभी पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया। बैठकों की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के उपाध्यक्ष व संचालन संयुक्त सचिव ने किया।

7. **सांस्कृतिक संध्या :-** शाम को श्री रजब अली भारती एवं साथी कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जिसने सभी शिक्षकों को भावविभोर कर दिया। संगठन ने सभी कलाकारों का आभार व्यक्त किया एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर उनका सम्मान किया।

8. **शैक्षिक संगोष्ठी सम्पन्न :-** अधिवेशन के दूसरे दिन 15 जनवरी को प्रात:9.15 बजे ''उच्च शिक्षा के उन्नयन में सूचना प्रौद्योगिकी की उपादेयता'' विषय पर शैक्षिक संगोष्ठी सम्पन्न हुई। शैक्षिक संगोष्ठी के संयोजक डॉ. राजेन्द्र शर्मा ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की उपादेयता है, अनुसंधान प्रकाशन, चिकित्सा, विज्ञान, कला, मानविकी, वाणिज्य, प्रशासनिक कार्य, खेल आदि में इसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है। प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली आदि सभी सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ऑनलाईन एवं कम समय में पूर्ण की जा रही है। वर्तमान में कागज-विहिन प्रबन्धन प्रारम्भ हो गया है। डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रौद्योगिकी में भौतिक दूरियाँ तो घटती जा रही हैं वहीं आत्मिक दूरियाँ बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अर्वाचीन नहीं, प्राचीन है। गुणवत्ता की कसौटी पर कस कर सूचना प्रौद्योगिकी की वर्तमान शिक्षा के उन्नयन में उपादेयता को देखने की आवश्यकता है। डॉ. ब्रजकुमार योगी ने कहा कि शोध व अनुसंधान में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विन्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक उपयोगी व कम खर्चे वाला है। लाइनेक्स को मुक्तरूप से वितरित किया जा सकता है। हमें कॉपी राइट से कॉपी लेफ्ट तंत्र की ओर बढ़ना होगा। ऑपन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग से हम मंहगे सॉफ्टवेयर के पायरेटेड़ वर्जन के गैर कानूनी उपयोग से भी बच सकते हैं। डॉ. सम्पूर्णानंद राकेचा ने लाइनेक्स की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इसमें 2000 से अधिक फ्लेवर है, ऑपन ऑफिस किसी भी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कमतर नहीं है। डॉ. नारायणलाल गुप्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी की उच्च शिक्षा में उपादेयता को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी ने वैश्विक नागरिक बनाने का काम तो किया है। प्रौद्योगिकी के कारण वरच्यूअल लैब, ऑन लाइन सोल्यूशन की बात होती है परन्तु क्या इससे मस्तिष्क का विकास हो रहा है, यह विचारणीय बिन्दु है। फेस बुक पर मित्र तो ढेरों है पर मित्रता का भाव लुप्त है। क्या सूचना प्रौद्योगिकी की उपादेयता निर्विवाद है यह मंथनीय विषय है। डॉ. योगेन्द्र भानू ने बताया कि इन्टरनेट पर कई भ्रामक जानकारियाँ है। मूलग्रंथों की विषय वस्तु को तोड़ मरोड़ कर अप्रासंगिक बनाने का काम इन्टरनेट द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री रविकुमार जी, सहसंयोजक, विश्व विभाग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कहा कि बायनरी सिस्टम का उल्लेख वेदों में भी है, बोधायन सूत्र में इसका अवलोकन किया जा सकता है, इसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी में आज किया जा रहा है। सूचना सम्प्रेषण प्रक्रिया में होने वाली त्रुटियों को पहचानने एवं संशोधन करने के लिए आज जो कोड़िंग प्रक्रिया अपनायी जा रही है उसका उपयोग सदियों पहले हमारे यहाँ वेदपाठी करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि घनपाठ का उपयोग ई-मेल में होता है। भारतीय सॉफ्टवेयर कर्मियों की विश्वभर में माँग है एवं उनके कार्य की पहचान हो रही है, यह

हमारे लिए गौरव की बात है इसरो ने सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट कैमरा बनाया है, जिसके द्वारा खींचे गये चित्रों का उपयोग अनुसंधान में विभिन्न देश कर रहे हैं। उन्होंने संस्कृत को सभी भाषाओं की मूल भाषा बताया व कहा कि लगभग 150 विदेशी विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन कराया जा रहा है। संस्कृत व्याकरण सबसे सशक्त व्याकरण है यह सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। इससे पूर्व संगठन अध्यक्ष ने श्री रविकुमारजी का परिचय कराया। शैक्षिक संगोष्ठी में शैक्षिक महासंघ के महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंघल, शैक्षिक मंथन के प्रधान सम्पादक प्रो. संतोष पाण्डे के अतिरिक्त अनेक शिक्षाविद उपस्थित थे।

9. **50वें प्रांतीय अधिवेशन का खुला सत्र सम्पन्न :-** 15 जनवरी को रुक्टा (रा.) के 50 वें प्रांतीय अधिवेशन का खुला सत्र व वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न हुई। इस सत्र में महामंत्री ने गत सत्र की गतिविधियों का विवरण देते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। महामंत्री ने सन् 2010-11 के अंकेक्षित आय-व्यय विवरण तथा 30 जून 2011 को समाप्त वर्ष के चिट्ठे (बैंलस शीट) को प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने अनुमोदित किया। महामंत्री प्रतिवेदन व आय-व्यय लेखे की प्रति संलग्न है। प्रतिनिधि सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव स्वीकार किये गये। इनमें पूर्व में पारित प्रस्तावों की पुन:पुष्टि करते हुए राज्य सरकार से आग्रह किया कि महाविद्यालयों में समग्र, सुव्यवस्थित, शैक्षिक वातावरण हेतु महाविद्यालयों में ढाँचागत सुविधाओं का विस्तार कर सभी प्रकार के रिक्त पड़े पदों को अविलम्ब भरा जाये, यू.जी.सी. के मापदण्डानुसार महाविद्यालयों में शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात सुनिश्चित किया जाये, शैक्षणिक संस्थाओं का समाज के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ शोधार्थियों के लिए उचित वातावरण व सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाये, ये सभी प्रस्ताव साधारण सभा में पारित किये गये। सभी प्रस्तावों की प्रति संलग्न है। गत अधिवेशन के पश्चात प्रो. सुमन नगेड़िया (अलवर), प्रो. महेश सिंघल (अलवर), प्रो. मधुकर श्याम चतुर्वेदी (जयपुर), प्रो. रामस्वरूप मीणा (अजमेर), प्रो. तोलाराम शर्मा (चूरू), प्रो. शैलबाला मिश्रा (भीलवाड़ा), प्रो. वी. एल. शर्मा (नवलगढ़), प्रो. महावीर सिंह यादव (चूरू), प्रो. जे. एम. खीची (कोटा), प्रो. एस. के. त्यागी (कोटा) एवं प्रो. के एम. इनाणी (कोटा) के असामायिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया।

10. **स्वर्ण जयंती अधिवेशन पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान :-** संगठन के 50वें अधिवेशन पर कोटा सहित राज्य के 36 सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। उन्हें श्रीफल, दुपट्टा, स्मृति चिह्न व स्मारिका की प्रति, प्रो. जे. पी. सिंघल, प्रो. संतोष पाण्डे व श्री रविकुमारजी ने भेंट की। शिक्षक समाज, व्यक्ति व राष्ट्र का निर्माता है उनके मार्ग दर्शन से ही समग्र विकास संभव है इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान व उनकी समस्याओं को उठाना रुक्टा (राष्ट्रीय) की रचनात्मक कार्यशैली को दर्शाता है।

11. **समारोप कार्यक्रम सम्पन्न :-** खुले अधिवेशन व सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान समारोह के पश्चात् समारोप कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। जिसकी अध्यक्षता प्रो. जे. पी. सिंघल ने की, मुख्य अतिथि श्री रविकुमारजी व विशिष्ट अतिथि प्रो. संतोष पाण्डे ने सभी का मार्गदर्शन किया। श्री रविकुमारजी ने कहा कि भारत के विद्यार्थी ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में अग्रणी है इसका श्रेय यहाँ के शिक्षकों को

जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे चितंन में सेवानिवृत्ति या retirement शब्द नहीं है, यहाँ तो प्रमोशन की बात होती है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यास आश्रम में सभी आश्रम प्रमोशन को इंगित करते हैं। उन्होंने श्रेष्ठ गुरुओं का उदाहरण देते हुए कहा कि गुरु में गुरुत्वाकर्षण होता है जिससे शिक्षार्थी उनके समीप आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रो. जे. पी. सिंघल ने कहा कि आज शिक्षा संक्रमण काल से गुजर रही है अत: शिक्षा की प्रणाली व नीति में समयानुसार परिवर्तन लाना होगा। प्रो. संतोष पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का समग्र विकास संभव होगा अत: शिक्षा के संदर्भ से प्राचीन व अर्वाचीन विचारों व प्रणालियों का हमें अध्ययन करना चाहिये। आयोजन सचिव एवं संगठन के महामंत्री ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया, राष्ट्रगान के साथ 50वाँ वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ।

12. **अधिवेशन हेतु अकादमिक अवकाश के आदेश जारी :-** रुक्टा (रा.) के 50वें प्रांतीय अधिवेशन में भाग लेने हेतु निदेशालय ने आदेश क्रमांक एफ/8/(17) रुक्टा (रा.)/अकाद/निकाशि/11/दिनांक 2-1-12/के तहत अकादमिक अवकाश के आदेश जारी किये हैं। इस आदेश के अनुसार अधिवेशन में प्राचार्यों, उपाचार्यों, सहायक निदेशकों, प्राध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं निदेशालय के अधिकारियों को अधिवेशन में भाग लेने पर विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा।
13. **अधिवेशन की सफलता हेतु शुभकामना संदेश :-** महामहिम राज्यपाल महोदय श्री शिवराजजी पाटिल, मुख्यमंत्री श्री अशोकजी गहलोत, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती वसुंधराराजे जी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दयारामजी परमार व वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रो. नरेशजी दाधीच ने 14 व 15 जनवरी 2012 को आयोजित रुक्टा (रा.) के 50वें स्वर्ण जयंती अधिवेशन के लिए महामंत्री को शुभकामना संदेश भेजा। संगठन उनका आभार व्यक्त करता है।
14. **अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को यू.जी.सी. वेतनमानों के संबंध में निर्देश :-** 1987 व 1998 के यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप राज्य सरकार ने आदेश जारी किये थे, जिनकी पालना सभी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को करनी थी, परन्तु अनेक महाविद्यालयों ने सभी प्रावधानों को लागू नहीं किया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज होने के बाद संबंधित महाविद्यालयों को निदेशालय ने निर्देशित किया है कि 1987 व 1998 के यू.जी.सी. वेतनमानों की पूर्ण रूप से लागू करना सुनिश्चित करें व निदेशालय द्वारा वांछित सूचना दिनांक 30-1-2012 तक निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय को प्रेषित करें। इस संबंध में निदेशालय ने प्रबंध समितियों को पत्र क्रमांक एफ/24( ) लेखा/अनु./निकाशि2011-12/1365-1453 दिनांक 26-12-211 के तहत निर्देशित किया है।
15. **अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति का स्वागत :-** महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नवनियुक्त कुलपति प्रो. रूपसिंह बारहठ का संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 27 जनवरी को उनसे मिलकर स्वागत किया तथा सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रतिनिधि मंडल में डॉ. मधुर मोहन रंगा, प्रो. बी. पी. सारस्वत, डॉ. नारायणलाल गुप्ता, डॉ. सुशीलकुमार बिस्सु सम्मिलित थे। उल्लेखनीय है कि संगठन पिछले काफी समय से शिक्षक कुलपति लगाने की मांग कर रहा था।
16. **सदस्यता प्राप्ति :-** इस सत्र की सदस्यता संख्या 2364 हो गई है। इकाई सचिवों/सदस्यों से आग्रह है कि वे शेष रहे सदस्यों की सदस्यता शीघ्र महामंत्री को भिजवाये।

प्रस्ताव

प्रस्ताव क्रं. 1 – रुक्टा (रा.) के 50वें अधिवेशन की यह साधारण सभा पूर्व में पारित उन सभी प्रस्तावों की पुनर्पुष्टि करती है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। साधारण सभा इन पर शीघ्र कार्यवाही का आग्रह करती है।

प्रस्ताव क्रं. 2 – रुक्टा (रा.) के 50वें प्रान्तीय अधिवेशन की साधारण सभा यह अनुभव करती है कि महाविद्यालयों में समग्र सुव्यवस्थित शैक्षिक वातावरण हेतु ढाँचागत सुविधाओं का अभाव है। अत: विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त स्तरीय कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, वाचनालय, सभागार, खेल के मैदान सहित स्तरीय खेल सामग्री, शिक्षकों के बैठने एवं अध्ययन हेतु उपयुक्त व्यवस्थाएं स्थापित की जायें। साथ ही सभी प्रकार के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जावे। इनके अभाव में उच्च शिक्षा का स्वस्थ विकास अवरुद्ध हो रहा है।

प्रस्ताव क्रं. 3 – विषय के सम्पूर्ण एवं प्रभावी सम्प्रेषण एवं शिक्षक-शिक्षार्थी के जीवन्त सम्पर्क की दृष्टि से यू.जी.सी. ने एक निर्धारित शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात तय किया हुआ है। राज्य में निरन्तर इसकी अवहेलना हो रही है और एक सैक्शन में विद्यार्थियों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है। रुक्टा (रा.) के 50वें अधिवेशन की साधारण सभा यह माँग करती है कि एक सैक्शन में विद्यार्थियों की संख्या यू.जी.सी. के मानदण्डानुसार रख कर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे।

प्रस्ताव क्रं. 4 – शैक्षिक संस्थाओं का समाज के साथ समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शोध कार्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अत: रुक्टा (रा.) के 50वें अधिवेशन की साधारण सभा यह माँग करती है कि राज्य के आर्थिक विकास की संभावनाओं व क्षमताओं का समुचित विकास करने की दृष्टि से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किये जाने वाले शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार समुचित वातावरण उत्पन्न करे एवं शोधार्थियों को उपयुक्त सहायता एवं सुविधायें अविलम्ब उपलब्ध करवाये।

प्रस्ताव क्रं. 5 – रुक्टा (रा.) के गत अधिवेशन के पश्चात शिक्षा जगत के हमारे अनेक साथी प्रभु तत्व में विलीन हो गये हैं। संगठन के 50वें अधिवेशन की यह साधारण सभा प्रो. सुमन नगेड़िया (अलवर), प्रो. महेश सिंघल (अलवर), प्रो. मधुकर श्याम चतुर्वेदी (जयपुर), प्रो. रामस्वरूप मीणा (अजमेर), प्रो. तोलाराम शर्मा (चूरू), प्रो. शैलबाला मिश्रा (भीलवाड़ा), प्रो. वी. एल. शर्मा (नवलगढ़), प्रो. महावीरसिंह यादव (चूरू), प्रो. जे. एस. खीची (कोटा), प्रो. एस. के. त्यागी (कोटा) एवं प्रो. के. एम. इनाणी (कोटा) के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इनकी सद्गति हेतु प्रार्थना करती है एवं परमपिता परमात्मा से कामना करती है कि इनके परिजनों को इस असह्य दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

भवदीय

(डॉ. मधुरमोहन रंगा)
[महामंत्री रुक्टा (रा.)]

के. 52
कृष्ण गंज, अजमेर-305 001 (राज.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

50वाँ प्रांतीय अधिवेशन, कोटा

दिनांक 14 व 15 जनवरी 2012

महामंत्री प्रतिवेदन

रूक्टा (राष्ट्रीय) का 49 वाँ प्रान्तीय अधिवेशन 15 व 16 मई 2011 को बी.डी.एम. विद्यापीठ बीबीरानी (अलवर) में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में प्रान्त के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व रहा। 49वें अधिवेशन के पश्चात् प्रमुख गतिविधियों एवं उपलब्धियों का विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिससे संगठन की सक्रियता, गतिशीलता एवं प्राप्त सफलताओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। राज्य के राजकीय, गैर राजकीय तथा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में यह संगठन निरन्तर अधिकांश शिक्षकों की सदस्यता वाला प्रांत का प्रतिनिधि संगठन है। 30 जून 2011 को समाप्त हुए शिक्षा सत्र में 2390 सदस्यों की इतनी सदस्यता वाला यह प्रांत का एकमेव संगठन है। विश्वास है कि इस आगामी सत्र के लिए 4000 की सदस्यता को हम सब अपनी सक्रियता के आधार पर न केवल प्राप्त करेंगे अपितु लक्ष्य से आगे भी निकलेंगे। संगठन के निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप कतिपय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है –

1. **अनुदानित महाविद्यालयों के 759 प्राध्यापकों का राजकीय क्षेत्र में आमेलन :-** पिछले कई वर्षों से अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षक अनुदान की कमी चलते नियमित रूप से वेतन एवं अन्य परिलाभों से वंचित चल रहे थे। संगठन ने लगातार उनकी समस्याओं एवं मांगों को प्रमुखता से उठाया। उनकी समस्याओं को लेकर राज्य सरकार से विभिन्न वार्ताओं एवं पत्रों के माध्यम से दबाव बनाया। इस विषय को लेकर 26 नवम्बर, 2010 को एक दिवसीय धरना भी सचिवालय के बाहर दिया गया। 49वें प्रांतीय अधिवेशन में भी प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से इस विषय पर अविलम्ब कार्यवाही का आग्रह किया गया। संगठन के निरन्तर सम्पर्क, प्रयास एवं दबाव से अन्ततः सरकार ने 29-7-2011 को अनुदानित महाविद्यालयों के 759 शिक्षकों के राजकीय सेवा में आमेलन के आदेश जारी कर दिये।
2. **प्राचार्य चार माह तक के विभिन्न अवकाश स्वीकृत करने हेतु अधिकृत :-** निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर ने दिनांक 6-6-2011 को जारी आदेश के द्वारा प्राचार्य को अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के चार माह के विभिन्न अवकाश स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया है। संगठन ने लगातार इस विषय में विभिन्न वार्ताओं एवं पत्रों में कार्यालयाध्यक्षों को चार माह के अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में राजस्थान सेवा नियम का संदर्भ दिया था। संगठन ने यह भी तर्क दिया कि शिक्षकों का सम्पूर्ण रिकार्ड महाविद्यालय में ही रहता है व प्राचार्य ही अवकाश स्वीकृत करते है तो प्रकरण निदेशालय भिजवाये जाने का औचित्य नहीं है। सरकार ने संगठन के पक्ष पर सहमति व्यक्त करते हुए आदेश प्रसारित किये।

3. **वरिष्ठ व चयनित वेतनमान में प्रोहत्सान स्वरूप देय अग्रिम वेतन वृद्धियों के लाभ की वसूली अग्रिम आदेशों तक स्थगित :-** निदेशालय कॉलेज शिक्षा ने दिनांक 26-8-2011 के आदेश के अंर्तगत प्राध्यापकों से अग्रिम वेतन वृद्धियों के विरुद्ध की जाने वाली वसूली को आगामी आदेशों तक स्थगित किया है। इससे पूर्व आयुक्तालय के आदेश दिनांक 2-3-2010 के तहत वरिष्ठ वेतनमान में यू.जी.सी. की अनुशंसाओं के अनुसार पीएच.डी. धारकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियों के लाभ दिये जाने पर चयनित वेतनमान की स्वीकृति के समय दी गई दो वेतन वृद्धियों की पुन: वसूली के आदेश जारी किये थे। संगठन ने इसका लगातार विरोध किया था, संगठन का स्पष्ट मत रहा है कि अग्रिम वेतन वृद्धियाँ यू.जी.सी. के अनुशंक्षायों के अनुसार प्रोत्साहन (incentive) है न कि दोहरा लाभ। इस विषय में मुख्यमंत्रीजी, शिक्षामंत्रीजी, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा व निदेशक कॉलेज शिक्षा से वार्ता की। राजस्थान विधानसभा में भी संगठन का पक्ष विधायकों ने तर्क सहित रखा। जिसकी परिणति में सरकार ने वरिष्ठ व चयनित वेतनमान में अग्रिम वेतन वृद्धियों के लाभ की वसूली को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया।
4. **पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों का नवीन यू. जी. सी. वेतनमान 2006 में वेतन निर्धारण :-** निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर ने दिनांक 26 अगस्त 2011 के आदेश के अर्न्तगत पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों के बकाया प्रकरणों का नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में वेतन निर्धारण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि इन रूके हुए वेतन निर्धारण प्रकरणों के निस्तारण हेतु संगठन लगातार प्रयत्नशील था।
5. **अनुदानित महाविद्यालयों को वित्तिय वर्ष 2011-12 के प्रोविजनल अनुदान सहायता राशि जारी करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ :-** अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा सत्र 2011-12 में की सेवा हेतु वेतन एवं अन्य परिलाभ राज्य सरकार द्वारा अनुदान जारी नहीं करने के कारण रुके हुए हैं, संगठन ने सरकार के समक्ष इस विषय को विभिन्न वार्ताओं एवं पत्रों के माध्यम से लगातार उठाया है। संगठन के प्रयास के फलस्वरूप सरकार ने यह राशि जारी करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।
6. **स्नातक व स्नातकोत्तर प्राचार्यों की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत :-** निदेशालय कॉलेज शिक्षा के नोटिफिकेशन दिनांक 12-10-2009 के अनुसरण में दिनांक 19-8-2011 को व दिनांक 8-9-2011 को 88 स्नातक व स्नातकोत्तर प्राचार्यों की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। इन अधिकारियों के समस्त रिकार्ड निदेशालय में ही रहते हैं अत: निदेशालय स्तर से ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होनी थी, जो काफी समय से लम्बित थी। संगठन ने इस विषय को उच्च अधिकारियों के समक्ष विभिन्न वार्ताओं में व पत्रों के माध्यम से उठाया था।
7. **संविदा व्याख्याताओं के वेतन भुगतान संबंधी आदेश :-** निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर ने दिनांक 16-8-2011 व 25-10-2011 को आदेश जारी कर संविदा व्याख्याताओं को 1-7-2010 से 30-4-2011 तक की अवधि का वेतन नवीन अनुबंध की शर्त को बाध्यकारी बनाये बिना भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है, दूसरे आदेश में 1-7-2011 से 31-12-2011 तक वेतन भुगतान किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है। संगठन संविदा व्याख्याताओं के नियमित वेतन भुगतान की मांग करता रहा है।

8. **राजकीय सेवा में आमेलित प्राध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का पदस्थापन :-** राज्य सरकार ने दिनांक 20-12-2011 को आदेश जारी कर सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय सेवा में आमेलित प्राध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के पदस्थापन के आदेश जारी किये हैं। संगठन ने लगातार इस विषय में सरकार से वार्ता की व पत्र लिखे। हाल ही में 16-12-2011 को भी उच्च शिक्षा मंत्रीजी से व्यक्तिश: वार्ता कर समायोजित प्राध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के शीघ्र पदस्थापन का अनुरोध किया था।

9. **अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित विभागीय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार प्राचार्य को :-** निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर ने दिनांक 21-12-2011 के आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित विभागीय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार प्राचार्य को प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रसारित दिनांक 4-8-2011 के आदेश में संशोधन की मांग संगठन ने की थी। इस संबंध में निदेशक जी से निवेदन किया था कि प्राचार्य को प्रभारी अधिकारी बनाने से महाविद्यालय के कार्य प्रभावित होते है, अत: प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार प्राचार्य को दिया जाना चाहिये, संगठन के तर्क से सहमत होकर सरकार ने संशोधित आदेश जारी किये है।

10. **कोटा विश्वविद्यालय के आचार्यों व सहायक आचार्यो के स्थायीकरण के आदेश जारी :-** कोटा विश्वविद्यालय के आचार्यों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिनांक 18-10-2011 व 4-11-2011 के द्वारा आचार्यों व सहायक आचार्यों के स्थायीकरण के आदेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के कार्य भार ग्रहण करने के बाद साढ़े तीन वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनके स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं हुए थे। इस संबंध में संगठन ने कुलाधिपति व कुलपति कोटा विश्वविद्यालय से उनके स्थायीकरण के आदेश जारी करने का आग्रह किया था ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार के परिलाभ व सुविधाएं मिल सके।

11. **पुस्तकालाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षा निदेशकों के वरिष्ठ व चयनित वेतनमान रिव्यू करने के आदेश** - निदेशालय कॉलेज शिक्षा ने पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों के वरिष्ठ/चयनित वेतनमान रिव्यू करने हेतु दिनांक 27-12-2011 को आदेश जारी किये हैं। उन आदेशों के तहत राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 27-7-1998 को कार्यरत इन अधिकारियों के वरिष्ठ/चयनित वेतनमान प्रकरणों को रिव्यू करना है। संगठन ने इस विषय का ध्यान राज्य सरकार को लगातार वार्ता व पत्रों के माध्यम से दिलाया था।

12. **महाविद्यालयों के पदनाम परिवर्तन के संदर्भ में प्रगति :-** संगठन के नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों के साथ साथ महाविद्यालयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर पदनाम देने तथा प्रोफेसर के पद सृजित करने संबंधी मांग को लगातार सरकार के समक्ष रखा, इस विषय में उच्च शिक्षा मंत्रीजी, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा व निदेशक कॉलेज शिक्षा से वार्ता की व पत्र भी लिखे। जिसकी परिणति में संगठन को प्राप्त जानकारी के अनुसार पद नाम परिवर्तन पर वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् प्रकरण डी.ओ. पी. के पास विचाराधीन है, नियम परिवर्तन की वैधानिक प्रक्रिया के पश्चात् पदनाम परिवर्तन हो सकेगा।

संगठनात्मक गतिविधियाँ

1. **अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों का राजकीय सेवा में आमेलन पर कार्यवाही** – अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर संगठन ने लगातार उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, निदेशक कॉलेज शिक्षा व उपशासन सचिव उच्च शिक्षा से मिलकर समस्याओं के निस्तारण का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने बजट भाषण में इन शिक्षकों का राजकीय सेवा में आमेलन हेतु बजट का प्रावधान रखा था। संगठन ने इस विषय पर राज्य सरकार से 12 मई, 19 मई, 8 जुलाई को वार्ता की तथा आमेलन की प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न कराने का आग्रह किया। 49वें प्रांतीय अधिवेशन के खुले सत्र में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से उस पर कार्यवाही करने का आग्रह किया। संगठन ने इस विषय पर सरकार से लगातार अनुरोध किया कि इन शिक्षकों को पाँचवें व छठे वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमानों व कॅरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देकर तथा इनके बकाया एरियर का शीघ्र भुगतान कर समायोजन किया जाय।
2. **राजकीय सेवा में आमेलित प्राध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों के पदस्थापन पर सरकार से वार्ता :-** राज्य सरकार ने 29-7-2011 को आदेश जारी कर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों का राजकीय सेवा में समायोजन किया था। दिनांक 4-8-2011 के आदेश के तहत निदेशालय ने इन्हें अभीमुखीकरण हेतु विभिन्न महाविद्यालयों में उपस्थिति देने के निर्देश दिये थे। संगठन ने लगातार वार्ता का क्रम जारी रखते हुए सरकार से इन शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के पदस्थापन की मांग की थी। 16-12-2011 को भी उच्च शिक्षा मंत्रीजी से वार्ता कर आग्रह किया था कि महाविद्यालयों में पद रिक्त होने के कारण अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है अत: समायोजित शिक्षकों का शीघ्र पदस्थापन करें।
3. **वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमानों की पात्रता में पूर्व/अन्यत्र की गई सेवा का समावेश :-** सम्पूर्ण देश में पूर्व अन्यत्र की गई सेवा का लाभ यू.जी.सी. वेतनमान योजना के अन्तर्गत प्रभावी हुआ। संगठन के अनवरत प्रयासों के बावजूद सार्थक परिणाम नहीं जारी होने से त्रस्त शिक्षकों ने माननीय न्यायालय का सहारा लिया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसके औचित्य को स्वीकार कर राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वरिष्ठ व चयनित वेतनमानों में पूर्व सेवा का लाभ दिया जाय। सर्वोच्य न्यायालय ने भी राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को निरस्त कर उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को सही माना। इस संबंध में संगठन ने 19 मई, 29 अगस्त, 8 नवम्बर व 16 दिसम्बर को वार्ता में सरकार से पुन: आग्रह किया है कि सरकार इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाकर सभी शिक्षकों को पूर्व सेवा का लाभ प्रदान करें।
4. **वेतनमानों एवं अन्य परिलाभों के संबंध में किये गये प्रयास :-** संगठन ने उच्च शिक्षामंत्रीजी, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक, प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा), निदेशक कॉलेज शिक्षा, उपशासन सचिव (उच्च शिक्षा) से विभिन्न व्यक्तिश: वार्ताओं एवं अलग से लिखे गये पत्रों के माध्यम से शिक्षकों के वेतन एवं अन्य परिलाभों से जुड़ी समस्याओं को सक्रियता पूर्वक उठाया। प्रमुख समस्याएं

जिन पर संगठन ने अविलम्ब कार्यवाही की मांग की है उनमें सहायक आचार्य एवं सह आचार्य का पदनाम देने, महाविद्यालयों में आचार्यों के पद सृजित करने, यू.जी.सी. एरियर का बकाया 40 प्रतिशत भुगतान नगद करने, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के वेतन निर्धारण एवं नवीन सी.ए.एस. का लाभ देने, राज्य एवं राज्य के बाहर सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृति का अधिकार प्राचार्यों को देने, राज्य के बाहर अकादमिक संस्थाओं निकायों, आयोगों में विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित होने पर शिक्षक को कर्त्तव्य पर मानने आदि शामिल है।

5. **जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन पुनः निर्धारण के प्रयास :-** नवीन यू.जी.सी. वेतनमान लागू होने के साथ ही 1 जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन पुनः निर्धारण में आ रही कठिनाईयों को लेकर रुक्टा (रा) के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, निदेशक कॉलेज शिक्षा व उपशासन सचिव उच्च शिक्षा से समय समय पर वार्ता की व पेंशन पुनः निर्धारण का आग्रह किया।
6. **प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक :-** रुक्टा (रा) के पदाधिकारियों की बैठक क्रमशः 24 जुलाई 2011, 13 नवम्बर 2011 व 14 जनवरी 2012 को हुई। जिसमें संगठन की विभिन्न गतिविधियों व आगामी कार्ययोजनाओं पर विचार किया।
7. **महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय इकाइयों में शिक्षकों से सम्पर्क :-** रुक्टा (रा.) के अध्यक्ष, महामंत्री, संगठनमंत्री, सहसंगठनमंत्री, प्रान्तीय कार्यकारिणी सदस्यों, विभागीय समितियों एवं प्रकोष्ठों के सदस्यों ने रूक्टा (रा.) की विभिन्न इकाइयों में बैठकों द्वारा शिक्षकों से सम्पर्क कर प्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्याओं, चिन्ताओं, एवं सुझावों को जाना व संगठन की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।
8. **सेवानिवृत शिक्षकों द्वारा आजीवन सदस्यता स्वीकार करना** - सेवानिवृत शिक्षकों से आग्रह किया गया था कि वे रूक्टा (रा) की आजीवन सदस्यता ग्रहण करें। हर्ष का विषय है कि कई सेवानिवृत शिक्षकों ने संगठन की आजीवन सदस्यता को स्वीकार किया है।
9. **महापुरुषों की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई :-** सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत महाराणा प्रताप जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। प्रातःकाल संगठन के पदाधिकारियों व सक्रिय कार्यकर्त्ताओं ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व शाम को संगोष्ठी में भाग लिया।
10. **अनुदानित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के सदस्यों के राजकीय सेवा में समायोजन हेतु आग्रह :-** राज्य सरकार ने 27.7.2011 को आदेश जारी कर राज्य के अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों का समायोजन राजकीय सेवा में करने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं। इसी क्रम में अनुदानित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के सदस्यों के आदेश भी अपेक्षित है। संगठन ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षामंत्री, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा व निदेशक कॉलेज शिक्षा से आग्रह किया है कि इस संबंध में अविलम्ब आदेश जारी किये जावें।

11. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व मानव संसाधन मंत्रालय से शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह :-** राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पास यू.जी.सी. के मेजर व माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट स्वीकृत है, शोधकर्ताओं के तबादलों के कारण शोध कार्य पर प्रतिगामी प्रभाव पड़ता है, संगठन ने अध्यक्ष यू.जी.सी. एवं मानव संसाधन विकास मंत्रीजी से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार को इस संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करे कि यथा संभव शोध निदेशकों के तबादले न करे। साथ ही यह भी निवेदन किया है कि सेवारत प्राध्यापकों को पीएच. डी. उपाधि हेतु कोर्स वर्क से मुक्त किया जाय।

12. **अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यक्रमों में सहभागिता :-** 4 व 5 जून को सतना (म. प्र.) में सम्पन्न अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, 21 अगस्त 2011 को उच्च शिक्षा संवर्ग के कार्यकर्त्ताओं की बैठक शिक्षक सदन दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों की सहभागिता रही। इसी प्रकार 4 व 5 नवम्बर को दिल्ली में सम्पन्न अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग में भी संगठन के कार्यकर्त्ताओं भाग लिया। रही। 6 नवम्बर को ही दिल्ली में सम्पन्न अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय साधारण सभा की बैठक में नवीन कार्यकारिणी का चयन किया गया। इसमें भी रुक्टा (रा.) के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा संवर्ग द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा की वर्तमान चुनौतियाँ विषय पर पटना (बिहार) में 17 व 18 दिसम्बर को संगोष्ठी सम्पन्न हुई, इसमें भी संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लेकर पत्र प्रस्तुत किये।

13. **विभागीय समितियों तथा प्रकोष्ठों का गठन :-** रुक्टा (रा.) के संगठनात्मक ढ़ाचे को पूर्ण करते हुए प्रकोष्ठों तथा विभागीय समितियों का गठन 24 जुलाई की कार्यकारिणी बैठक में किया गया।

14. **49 वें प्रांतीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर कार्यवाही :-** संगठन ने 49वें प्रांतीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर मुख्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा निदेशक कॉलेज से शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह किया। समय-समय पर उच्च अधिकारियों से वार्ता के समय भी इन प्रस्तावों पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

15. **विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं पर कार्यवाही :-** कोटा विश्वविद्यालय के आचार्यों, सहायक आचार्यों के स्थायीकरण के आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी नहीं करने पर कुलाधिपति व कुलपति जी से आग्रह किया। राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों को छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान अभी भी अपेक्षित है, इस संबंध में संगठन ने कुलाधिपति, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपतियों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिख कर शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुचित अतिरिक्त आवासीय किराया कटौती के पुन: भुगतान के संबंध में भी कुलपति जोधपुर विश्वविद्यालय को पत्र लिख कर व वार्ता करके शीघ्र भुगतान का अनुरोध किया है।

16. **जनगणना 2011 में व्याख्याताओं की ड्यूटी पद की गरिमा के विपरीत लगाने पर कार्यवाही :-** राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों को ड्यूटी मास्टर ट्रेनर के रूप में लगाने का विरोध किया है, इस संबंध में संगठन ने निदेशक जनगणना को पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि यह न तो विधि सम्मत है और न ही प्रोटोकोल के अनुसार है अत: इस प्रकार की ड्यूटी को अविलम्ब निरस्त किया जाय।

17. **शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानान्तरणों का विरोध :-** राज्य सरकार द्वारा शिक्षा सत्र के मध्य में दिनांक 20-12-2011 को आदेश जारी कर 52 व्याख्याताओं के स्थानांतरण आदेश जारी किये हैं। संगठन सत्र के मध्य में किये गये इन अविवेकपूर्ण स्थानान्तरणों का विरोध किया एवं सरकार से आग्रह किया कि व्याख्याताओं की इच्छा के विपरीत किये गये सभी स्थानांतरण निरस्त किये जावे।

18. **अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में यू.जी.सी. वेतनमान 17/6/87 व 27-7-1998 के आदेशों को लागू करने पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर कार्यवाही :-** राजस्थान राज्य बनाम सेठ मोतीलाल महाविद्यालय प्रबंध समिति झुन्झुनु के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका को निरस्त कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया है। माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि बकाया राशि का भुगतान 15-12-2011 तक किया जाय। संगठन इस संबंध में राज्य सरकार को शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

19. **उच्च शिक्षा संस्थाओं का वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य एवं उनके उन्नयन के प्रयास (उच्च शिक्षा के बाजारीकरण के संदर्भ में) विषय पर संगोष्ठी :-** रूक्टा (रा) द्वारा 18-12-2011 को उच्च शिक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन भीलवाड़ा में किया गया। इसमें 15 शिक्षकों ने पत्र वाचन किया व अपने विचार रखे। उच्च शिक्षा के बाजारीकरण के संबंध में चिंता व्यक्त की गई व शिक्षा के आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन करने, संकाय सदस्यों के पुन:श्चर्या कार्यक्रम आयोजित करने, ज्ञान केन्द्रों के विकास, शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने, शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने संबंधी सुझाव सदस्यों ने दिये।

20. **यू.जी.सी. वेतनमान की अविभाज्य व्यवस्था में पी.एच.डी./एम.फिल. उपाधिधारियों को प्रोहत्सान स्वरूप प्रदत्त अतिरिक्त वेतन वृद्धि के प्रावधान के राज्यादेश की वापसी को निरस्त कर पूर्व राज्यादेश को पुन: प्रभावी बनाने पर कार्यवाही** - संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि 6 मई 2002 के आदेश को वापिस लेकर यू.जी.सी. के अनुशंषाओं के अनुरूप पूर्ववर्ती न्याय संगत आदेश को प्रभावी बनाया जाय तथा इसका लाभ सभी शिक्षकों को प्रदान किया जाय। इस विषय को वार्ता व पत्रों के माध्यम से शिक्षामंत्री जी, प्रमुख शासन सचिव व निदेशक कॉलेज शिक्षा के समक्ष रखा।

चुनौतियाँ

संगठन द्वारा निरन्तर की गई गतिविधियों, कार्यक्रमों, प्रदर्शनों, भेंटवार्ताओं एवं ज्ञापनों के परिणाम स्वरूप कई सफलताएं मिली हैं। कुछ समस्याओं का समाधान भी हुआ है तथापि बहुत-सी चुनौतियाँ बाकी हैं इनमें प्रमुख रूप से निम्न हैं :-

(1) एरियर का बकाया 40 प्रतिशत भुगतान
(2) पदनाम परिवर्तन
(3) शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की संशोधित डी.पी.सी.
(4) पूर्व व अन्यत्र सेवा का लाभ
(5) दिनांक 6 मई 2002 के एम.फिल., पीएच.डी. के लिए प्रोहत्सान स्वरूप देय अग्रिम वेतनवृद्धि पर रोक के आदेश को निरस्त करवाना
(6) निदेशक पद पर महाविद्यालय शिक्षा से डी. पी. सी. द्वारा पदस्थापन
(7) परिवीक्षा काल के प्रारंभ से ही स्थायी सेवा के सम्पूर्ण परिलाभ देना
(8) शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा संवर्ग में शामिल करना
(9) समायोजित शिक्षकों का राजकीय सेवा में कार्यरत शिक्षकों के समान सम्पूर्ण परिलाभ
(10) कृषिसंकाय के शिक्षकों का राजकीय सेवा में समायोजन
(11) विश्वविद्यालय शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर का भुगतान।

संगठन की उपर्युक्त गतिविधियों का संचालन एवं सफलताएं आप सभी के सक्रिय सहयोग व मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। आशा है आगे भी लम्बित समस्याओं का समाधान अपनी सक्रियता व सजगता के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे। जो कमियाँ रही हैं उनका कारण मेरी स्वयं की योग्यता एवं क्षमता की सीमाएं रहीं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रांतीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों, विभागीय समितियों के पदाधिकारियों, प्रकोष्ठों के प्रभारी व सदस्यों इकाई सचिवों तथा सभी सक्रिय सदस्यों के प्रति उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु हार्दिक आभार। साथ ही कामना करता हूँ कि आप सभी का सहयोग संगठन को सतत् मिलता रहेगा

भवदीय

(डॉ. मधुरमोहन रंगा)
[महामंत्री रुक्टा (रा.)]

के. 52
कृष्ण गंज, अजमेर-305 001 (राज.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

आय-व्यय खाता

(30 जून 2011 को समाप्त वर्ष के लिए)

इकाइयों को सहायता	48,020-00	सदस्यता प्राप्ति			
डाक व्यय	18,841-00	2009-2010	2400-00		
दूरभाष व मोबाईल	22,129-00	2010-2011	1,89,680-00		
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	19065-00				1,92,080-00
यात्रा व्यय	26701-00	इकाइयों का अंश	48,020-00		
फोटो स्टेट व टाइप	447-00	इकाइयों से विशेष सहायता	8,440-00		
पारिश्रमिक	6000-00	स्थायी जमा खाते पर ब्याज	38,435-00		
विविध	75,302-00	बचत खाते पर ब्याज	2,132-00		
ABRSM संबद्धता	2304-00	आजीवन सदस्यता	18,000-00		
आय का व्यय पर आधिक्य	88338-00				
	3,07,147-00				3,07,147-00

चिट्ठा 30 जून 2011

आय का व्यय पर आधिक्य			रोकड़ बचत बैंक खाता		
गत वर्षों का	15,84,352-20		ICICI	यूको	
इस वर्ष का आधिक्य	88,338-00		5976-00	74015-00	
		16,72,690-20			79,991-00
महामंत्री को देने बाकी	46,544-80		मियादी जमा खाता		
			ICICI	यूको	
			8,29,753 +	8,09,491	16,39,244-00
		17,19,235-00			17,19,235-00

हस्ताक्षर

डॉ. ग्यारसीलाल जाट

अध्यक्ष

हस्ताक्षर

डॉ. मधुर मोहन रंगा

महामंत्री

Certified that I have audited the accounts books and income and expenditure account and balance sheet of RUCTA (R.) for the period ending 30th June 2011 and report that I have obtained all information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit. In my opinion and to the best of my information and explanation given to me, the balance sheet gives true and fair view of the Association on 30th June 2011 and excess of income over expenditure for the year ended on that date.

(Dr. S. K. Bhojak)
Auditor